

जिसके पास अच्छा दोस्त है उसे किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं है।
- अज्ञात



जबर्दस्त जीत से रास्ता खुला

प्रधानमंत्री जॉनसन का भारत के प्रति सकारात्मक रवैया जगजाहिर है। बहरहाल शानदार जीत के बाद जॉनसन के सामने कई नई चुनौतियां भी आने वाली हैं। सबसे पहले तो ब्रिटेन को एकजुट रखने का मामला है।

मनीषा गुरुरानी

ब्रिटेन में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को मिली जबर्दस्त जीत से वहां अनिश्चितता के बादल काफी हद तक छंट गए हैं। अब ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का रास्ता खुल गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें जो जनादेश मिला है, उससे वे ब्रेकिजट डील लागू करवाएंगे और ब्रिटेन को एकजुट करेंगे। ब्रिटिश संसद के 650 सदस्यीय निम्न सदन हाउस आफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से 39 अधिक है। यह चुनाव ब्रेकिजट के मुद्दे पर लड़ा गया था। जॉनसन का नारा था— ब्रेकिजट होगा।

दरअसल ब्रेकिजट के मुद्दे पर लंबे समय से जारी उठापटक से वहां के लोग उकता गए थे। यह इलेक्शन उनके लिए आर या पार का मामला बन गया था और उन्होंने समस्या के निर्णायक समाधान के लिए

जॉनसन की झोली भर दी। यही वजह है कि ब्रेकिजट पर सवाल उठाने वाली विपक्षी लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि लेबर पार्टी समेत कई दलों ने संसद में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया था। इसी के बाद जॉनसन ने इस उम्मीद के साथ मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया था कि वह चुनाव जीतकर 31 जनवरी को 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन से अपने देश को अलग करने में सफल होंगे।

उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सिर्फ उनकी ही पार्टी देश को ब्रेकिजट के जाल से निकाल सकती है जबकि जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने वादा किया था कि वह ब्रेकिजट पर दोबारा जनमत संग्रह कराएगी। भारत की



दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि जहां सभी 12 भारतवंशी सांसदों ने अपनी सीटें बरकरार रखी वहीं तीन नए सांसद भी चुनकर आए। प्रधानमंत्री जॉनसन का भारत के प्रति सकारात्मक रवैया जगजाहिर है। बहरहाल शानदार जीत के बाद जॉनसन के सामने कई नई चुनौतियां भी आने वाली हैं। सबसे पहले तो ब्रिटेन को एकजुट रखने का मामला है। स्कॉटलैंड में उलटी हवा चल रही है। वहां चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को

भारी पराजय का सामना करना पड़ा है जबकि राष्ट्रवादी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) को शानदार जीत मिली है, जिसका साफ इशारा है कि वहां की बहुसंख्य जनता न केवल यूरोपीय संघ में रहना चाहती है बल्कि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग भी होना चाहती है। अगर स्कॉटलैंड में आजादी की मांग तेज हुई तो उत्तर आयरलैंड में भी यही भावना मजबूत हो सकती है। वहां अलगाववाद की आग तो दशकों से भड़की हुई है। इसके अलावा आर्थिक मसले भी हैं। आशंका है कि कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्रिटेन की बजाय यूरोपीय संघ को न तरजीह देने लें। ऐसा हुआ तो ब्रिटेन में आर्थिक संकट बढ़ सकता है और बेरोजगारी फैल सकती है। देखना है जॉनसन इन उलझनों को कैसे सुलझाते हैं।

ध्वनि कंपन

मनमोहन। शब्द अक्षरों से बने होते हैं और अक्षर कुछ और नहीं बल्कि ध्वनि कंपन है।

धर्म-दर्शन



अगर शब्द भगवान की तरह शक्तिशाली होते तो ये अक्षर ही भगवान की ताकत का कारण होते। शब्दों का यही महत्व है। समस्या शब्दों में नहीं होती बल्कि उसके वास्तविक प्रकृति की अज्ञानता के कारण होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमें दैनिक कामों में इन शब्दों की आवश्यकता होती है लेकिन जब हम उसकी ताकत को समझ लेते हैं तो हम सावधानी के साथ सुनना और बुद्धिमत्ता के साथ उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं। वास्तव में, हमारे जीवन में एक तीखी जुबान और लापरवाह श्रव्यता के कारण सारी समस्याएं होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिव सूत्र में प्रयुक्त संस्कृत शब्द 'मातृका' शब्दों की ताकत का वर्णन करता है और इसका अर्थ होता है छोटा गर्भ।

संपादकीय

अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त

संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह फुजैरा में सऊदी अरब के दो समुद्री तेल टैंकरों पर हमले की घटना चिंताजनक है। उनमें से एक सऊदी अरब से तेल लेकर अमेरिका के लिए रवाना होने वाला था। इसके अलावा यूएई ने दो नावों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही है। अमेरिका ने इसके लिए ईरान और उसके सहयोगी देशों—संगठनों को जिम्मेवार बताते हुए कहा है वे प्रॉक्सी वॉर के तहत ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस हमले पर चिंता जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

गौरतलब है कि फुजैरा बंदरगाह होर्मुज जलमार्ग से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से विश्व के एक तिहाई तेल और गैस का निर्यात होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ हुआ बहुपक्षीय व्यापार समझौता एकतरफा तौर पर खारिज कर दिए जाने और ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने के बाद से ही ईरान यह कहता रहा है कि अमेरिका ने उस पर ज्यादा दबाव बढ़ाया तो वह होर्मुज जलमार्ग को बंद कर देगा। इस आशंका के तहत ही अमेरिका ने पिछले दिनों इस क्षेत्र में अब्राहम लिंकन युद्धपोत और बी-52 बमवर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। ईरान के प्रमुख सैनिक संगठन इस्लामिक रिवाल्यूशनरी गार्ड्स कोर को अमेरिका आतंकी संगठन करार दे चुका है। जवाब में ईरान ने अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व में स्थित आतंकी बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी ईरान तेल उत्पादन में शीर्ष पर है। उसके तेल निर्यात पर पूरी रोक के लिए अमेरिका बाकी देशों से मिलकर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने के बाद ईरानी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो चली है।

ममता से आशा थी कि वह एक उदार और सहनशील राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेगी पर इस आशा का व्यवहार में उतरना अभी बाकी है।

इमीग्रेशन में तरजीह

अमित अग्रवाल

इस बार पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव के हर चरण में हिंसा की खबरें आई हैं। कुछ समय पहले पंचायत चुनाव के दौरान भी भारी हिंसा हुई थी। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ और लड़ाई-झगड़े के बीच प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति चकनाचूर हो गई। इसके लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। बंगाल अपनी समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है। पिछले दो सौ वर्षों में उसने कई बार देश को दिशा दिखाई है। राजनीतिक हिंसा ऐसे सुसंस्कृत राज्य की पहचान बन जाना क्षोभ और आश्चर्य का विषय है।

वैसे, बंगाली जनमानस में अपने विचारों को लेकर मर-मिटने का भाव शुरू से रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान वहां राष्ट्रवाद की लहर मजबूत हुई तो किशोर वय के कई क्रांतिकारी सामने आए जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में आत्म बलिदान की एक श्रृंखला रच दी। आजादी के बाद यह आदर्शवाद सबसे ज्यादा उग्र वाम विचारों में प्रतिबिंबित हुआ। दुर्भाग्यवश, विचार के प्रति उस रूमानी लगाव



को एक नई रचनात्मक ऊर्जा में रूपांतरित नहीं किया जा सका और धीरे-धीरे यह सत्ता से जुड़ी वैचारिक कट्टरता में बदलता गया। विरोधी विचार को सहन न करने और उसे हिंसक तरीके से

दबाने की प्रवृत्ति सबसे पहले 1990 के दशक में देखने को मिली, हालांकि चुनावी मंचों से लेपट के 30 सालों के शासन में 28 हजार राजनीतिक हत्याओं का आंकड़ा बताया जाता रहा है। हिंसा के ज्यादातर शिकार विरोधी दलों के कार्यकर्ता ही हुए। कम्युनिस्ट शासन के दौरान ममता बनर्जी को बालों से पकड़ कर राज्य सचिवालय से बाहर फेंकवाए जाने की कहानियां भी कही जाती रही हैं। ममता से आशा थी कि वह एक उदार और सहनशील राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेगी पर इस आशा का व्यवहार में उतरना अभी बाकी है।

राजनीतिक हत्याएं उनके शासन में भी जारी हैं। अभी बीजेपी को लगता है कि टीएमसी को उसी की आक्रामक शैली में जवाब देकर शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन दोनों के टकराव से राज्य का भारी नुकसान हो रहा है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य में पारंपरिक उद्योग-धंधे बंद हो चुके हैं और नए आ नहीं रहे। एक समय देश भर से लोग रोजी-रोटी के लिए बंगाल पहुंचते थे लेकिन आज वहां के लोग जीविका के लिए अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को अगर इस राज्य के भविष्य की जरा भी फिक्र है तो चुनाव के दौरान उन्हें अपना आचरण सम्यक् रखना चाहिए।

अष्टयोग-4895

7	5	2			
	38	32	1	27	
4	3		6		2
	29	2	45		33
1	3		5		4
	24	1	36	4	30
6		4	7		5
					3

प्रस्तुत खेल सुटोक् व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, गहरे काले वर्ण में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्णों की संख्या का कुल योग होगी, सीधे अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है।

अपना ब्लॉग

पश्चिम का प्रभाव

उमेश चतुर्वेदी। उन दिनों तब

की राज्य-व्यवस्था को संचालित कर रही कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जैसे सवाल उठे थे, ठीक सात साल बाद तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर वैसे ही सवाल मौजूदा शासक दलों पर उठ रहे हैं। सामुदायिक विकास और अपराधों-अनाचारों की कहानियां समानांतर घटित होती रही हैं। राज्य व्यवस्था और समाज अनाचारों को रोकने के लिए अपनी संस्कृति के मुताबिक कदम भी उठाते रहे हैं। भारतीय परंपरा में देखें तो समस्याओं से जूझने के लिए सामुदायिक स्तर पर कहीं ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जाते रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। जिन अभिय सवालों से सामुदायिक स्तर पर मुठभेड़ की जानी चाहिए थी, उन्हें हमने राज्य व्यवस्था को सौंप दिया है। इसीलिए जब भी हत्या, बलात्कार या कोई दूसरा अनाचार होता है, हम सिर्फ राज्य व्यवस्था को कौंसते हैं। उसे ही जवाबदेह ठहराते हैं। तब हमारा ध्यान निरंतरता के प्रतीक अपने प्रशासनिक तंत्र पर कम जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपने राजनीतिक नेतृत्व को बदलने का मौका जरूर मिलता है।

